Functioning of Commercial banks in Arunachal Pradesh

1263. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of commercial banks functioning in the country;

(b) the number of such public sector banks functioning in Arunachal Pradesh;

(c) whether these public sector banks have achieved their target fixed for a certain period for granting and distributing loans to needy people; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROS AD PAL): (a) and (b) Reserve banks of India (RBI) has reported that 282 scheduled commercial banks including 27 public sector banks were functioning in the country as at the end of June 1995 and of those 27 public sector banks, 5 banks were functioning inArunachal Pradesh.

(c) and (d) The details of the targets and achievements under Annual Credit Plan, 1994-95 for Arunachal Pradesh are given below:—

(Amount Rs. crores)

	Target	Achieve-ment
Agriculture	6.51	2.50
SSI	1.66	0.57
Services	3.90	3.96
Total Priority Sector	12.07	7.03

बाहरी देशों में भारतीय खाताधारक

1264.**श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** :

श्री चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि अनेक भारतीय नागरिक विदेशी बैंकों में खाताधारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा करायी गयी धनराशि का पता लगाने के लिये कोई प्रयास किया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) दिनांक 17 जुलाई, 1992 की अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, भारत सरकार ने 18.4.1992 से भारत वापस आने वाले भारतीय मूल के आनिवासी व्यक्तियों को विदेशों में उनके द्वारा खोले गए खातों के संचालन और रख-रखाव की अनुमति दी हैं बशर्ते कि वे एक वर्ष से अधिक समय भारत के बाहर रहे हों। उन्हे अथ्यर्पण/घोषणा की औपचारिकताओं से छूट दी गई हैं।

उपर्युक्त को देखते हुये, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उनके लिए भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा विदेशों में विदेशी मुद्रा खातों में जमा की गई राशि का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं होगा।

पनबिजली क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

1265. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या यह सच हैं कि देश में पनबिजली क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता 84,000 मेगावाट हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि अभी तक पनबिजली क्षेत्र में कुल 20,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ड.) क्या यह भी सच हैं कि पनबिजली क्षेत्र में विद्युत उत्पादन कुल विद्युत उत्पादन का 26 से 30 प्रतिशत हैं जबकि विशेषज्ञ समिति की राय में यह प्रतिशतता 40 होना चाहिये; और

(च) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने देश में उपलब्ध मितव्ययी से दोहन की जाने वाली जल-विद्युत शक्तया का मूल्यांकन

60 प्रतिशत भार अनुपात पर 84,044 मे.वा. किया हैं। यह लगभग 1,50,000 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमा के अनुपात होगी।

(ग) और (घ) इस समय देश में अधिष्ठापित जल-विद्युत उत्पादन क्षमता 20,835 मे.वा. हैं।

(ड.) और (च) भारत में व्यस्ततमकालीन और गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों में विद्युत के लिए मांग में काफी भिन्नता हैं। इस भिन्नता के कारणा विद्युत प्रणाली के प्रचालन को किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए आठवीं योजना में जल-विद्युत क्षमता अभिवृद्वि को और आगे बढ़ाने को परिकल्पना की गई हैं, ताकि 9वीं योजना के अंत तक कुल उत्पादन क्षमता अभिवृद्वि को और आगे बढ़ाने को परिकल्पना की गई हैं, ताकि 9वीं योजना के अंत तक कुल उत्पादन क्षमता में जल-विद्युत का 40% हिस्सा प्राप्त किया जा सके।

Norms for Backing Down of Units during off-peak hours

1266. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI MD. SALIM:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether any norms is being fixed for banking down of units during off-peak hours in view of the multiplicity of agencies for generation viz. central, State and IPP;

(b) if so, the details of proposed norms and the mode of this implementation; and

(c) if not, the steps proposed by Government to ensure normative justice to all generating agencies during off-peak period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) Banking down of units during off peak hours is resorted to during high frequency operation and at present is decided by mutual agreement among contributors to the Regional Electricity Boards. The practices followed varies from one region to other depending upon operational needs. Generally, it is based on a broad principle in which the costlier modes of generation like gas and liquid fuel turbines etc. are first taken out, followed by backing down by hydro stations with reservoirs (where water can be stored to be used during peak periods) where after generation output of other thermal units is reduced to a level till oil support is not required. The National Task Fore set up under the chairmanship of Chairman, CEA is, interalia, also examined this aspect of grid operations.

Irregularities in the Export of Textiles

1267. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether bids of export of Indian textiles have been highly invoiced whereas cotton in the international market is available at much lower rates; if so, the reasons therefor;

(b) whether over-invoicing of exports is made to save tax so that excess payment can be kept abroad to be brought back at a latter stage which is a clear case of indulging in Hawala and which results in prominent exporters being deprived of their legitimate rights;

(c) whether Government propose to investigate the matter to bring the culprits to book; and

(d) the amount of money involved in such Hawala?

THE MINISTER OF LABOUR AND THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Government do not have any information about over invoicing of export of textiles. However, the cotton prices in the international market are higher than the domestic cotton prices.

(c) and (d) Do not arise.

Meeting of Southern Regional Electricity Boards

1268. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether a meeting of the Chairman of Southern Regional Electricity Boards